



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 350]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/KARTIKA 14, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 नवम्बर, 2019

मामला सं. ओ आई (सी वी डी)-6/2019

विषय: इंडोनेशिया, मलेशिया, श्री लंका, थाईलैंड और वियतनाम से फाइबर बोर्ड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/17//2019- डीजीटीआर.—जबकि ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाई बोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और रुशिल डेकोर लिमिटेड (जिन्हें यहां "याचिकाकर्ता" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें यहां संबद्ध देश कहा गया है) से फाइबर बोर्ड्स (जिन्हें यहां संबद्ध वस्तु कहा गया है) के सन्निडाइजेशन का आरोप लगाते हुए समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1957 (जिसे यहां अधिनियम कहा गया है और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ/सहायिकी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्कों को लागू करने के लिए एक पाटन रोधी जांच की शुरुआत के लिए अनुरोध किया है।

क. सहायिकी प्राप्त करने (सन्निडाइजेशन) का आरोप

- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों ने सरकार के विभिन्न प्रोविंसों और म्युनिसिपैलिटीज, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य "सार्वजनिक निकायों" सहित संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराई गई कार्रवाई योग्य सन्निडी से लाभ प्राप्त किया है। याचिकाकर्ताओं

ने पब्लिक डोमेन में यथा-उपलब्ध और अन्य जांच प्राधिकरण जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जांच आयोजित की हैं और प्रतिकारी शुल्क योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों का अस्तित्व समाप्त किया है, के निर्धारण में संगत सरकारी एजेंसियों और सरकारी निकायों के संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं का सहारा लिया है।

ख. परामर्श

सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर करार (ए एस सी एम), के अनुच्छेद 13 की शर्तों में, इंडोनेशिया सरकार, मलेशिया सरकार, श्री लंका सरकार, थाईलैंड सरकार और वियतनाम सरकार को जांच शुरुआत पूर्व परामर्शों के लिए आमंत्रण भेजे गए थे। जहां क्रमशः 9, 10 और 11 अक्टूबर, 2019 को मलेशिया सरकार (जी ओ एम), इंडोनेशिया सरकार (जी ओ आई) और वियतनाम सरकार (जी ओ वी) के साथ परामर्श आयोजित किए गए थे, थाईलैंड सरकार ने परामर्शों के अवसर का लाभ नहीं उठाया। उत्तर देने वाले संबद्ध देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों के लिखित अनुरोध को रिकार्ड पर लिया है।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं कि संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों या/और उनसे संबंधित सरकारी निकायों द्वारा प्रदत्त बड़ी संख्या में सब्सिडी स्कीमों/कार्यक्रमों से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों ने निम्नानुसार लाभ प्राप्त किया है -

क. इंडोनेशिया सरकार द्वारा जारी योजनाएं -

- i. कार्यक्रम 1: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए स्थायी टिंबर का प्रावधान
- ii. कार्यक्रम 2: लॉग निर्यातों का सरकारी निषेध
- iii. कार्यक्रम 3: इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा के लिए लाभ
- iv. कार्यक्रम 4: आयकर की कमी
- v. कार्यक्रम 5: आयात शुल्क की छूट
- vi. कार्यक्रम 6: आयात शुल्क- कच्ची सामग्री की छूट
- vii. कार्यक्रम 7: वैट की छूट
- viii. कार्यक्रम 8: त्वरित मूल्यहास या ऋण मुक्ति
- ix. कार्यक्रम 9: भूमि एवं भवन कर से राहत

ख. मलेशिया सरकार द्वारा जारी योजनाएं -

- i. कार्यक्रम सं. 1: बाजार विकास अनुदान
- ii. कार्यक्रम सं. 2: निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त पोषण
- iii. कार्यक्रम सं. 3: क्रय कर्ता क्रेडिट गारंटी
- iv. कार्यक्रम सं. 4: प्रथम अन्वेषक (पायनियर) की स्थिति
- v. कार्यक्रम सं. 5: निवेश कर नीतियां
- vi. कार्यक्रम सं. 6: पुनर्निवेश भत्ता

- vii. कार्यक्रम सं. 7: त्वरित पूंजी भत्ता
- viii. कार्यक्रम सं. 8: टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन
- ix. कार्यक्रम सं. 9: संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ते
- x. कार्यक्रम सं. 10: ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विनिर्माण और विनिर्माण संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
- xi. कार्यक्रम सं. 11: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर शुल्क वापसी
- xii. कार्यक्रम सं. 12: बिक्री कर छूट
- xiii. कार्यक्रम सं. 13: कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्कों से छूट
- xiv. कार्यक्रम सं. 14: निर्यातों के संवर्द्धन के लिए दोहरी कटौती
- xv. कार्यक्रम सं. 16: लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
- xvi. कार्यक्रम सं. 17: बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता
- xvii. कार्यक्रम सं. 18: मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातकों के लिए कर छूट

ग. लंका सरकार द्वारा जारी योजनाएं –

- i. कार्यक्रम सं. 1: राष्ट्रीय भवन निर्माण कर छूट (अप्रत्यक्ष कर)
- ii. कार्यक्रम सं. 2: पूंजी और माध्यमिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट
- iii. कार्यक्रम सं. 3: विशिष्ट उपक्रमों के लिए आयात कर रियायत
- iv. कार्यक्रम सं. 4: उच्च निवेशों के साथ उपक्रमों के लिए आयकर छूट
- v. कार्यक्रम सं. 5: राष्ट्रीय उर्वरक सब्सिडी योजना
- vi. कार्यक्रम सं. 6: रबर प्लांटेशन के लिए सब्सिडी

घ. थाईलैंड सरकार द्वारा योजनाएं –

- i. कार्यक्रम सं. 1: मशीनरी पर आयात शुल्कों की छूट/कमी
- ii. कार्यक्रम सं. 2: निर्यात के लिए उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्कों की छूट
- iii. कार्यक्रम सं. 3: कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्कों की कटौती
- iv. कार्यक्रम सं. 4: बी ओ आई – प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए निगमित आयकर की छूट
- v. कार्यक्रम सं. 5: निवेश प्रोत्साहन क्षेत्रों में आयकर की कमी
- vi. कार्यक्रम सं. 6: सुविधाओं की स्थापना या निर्माण की लागत के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत कटौती
- vii. कार्यक्रम सं. 7: निवेश प्रोत्साहन क्षेत्रों में कंपनियों के लिए उपलब्ध दोहरी कटौती

- viii. कार्यक्रम सं. 8: आयकर की छूट - लाभांश
- ix. कार्यक्रम सं. 9: निर्यातों पर वैट छूट
- x. कार्यक्रम सं. 10: अल्पावधिक निर्यात क्रेडिट बीमा
- xi. कार्यक्रम सं. 11: मध्यम और दीर्घावधिक निर्यात क्रेडिट बीमा

ड. वियतनाम सरकार द्वारा योजनाएं –

- i. कार्यक्रम सं. 1: वस्तुएं निर्यात करने के लिए कच्ची सामग्रियों के आयातों पर आयात शुल्क छूट
 - ii. कार्यक्रम सं. 2: टैरिफ मुक्त क्षेत्रों में आयातित कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क छूट
 - iii. कार्यक्रम सं. 3: औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों के लिए फालतू पुर्जों और एसेसरीज के आयातों पर आयात शुल्क छूट
 - iv. कार्यक्रम सं. 4: निगमित आय कर की कटौती
 - v. कार्यक्रम सं. 5: आयकर की छूट या कटौती
 - vi. कार्यक्रम सं. 6: भूमि और जल किराए की छूट और कटौती
 - vii. कार्यक्रम सं. 8: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा निवेश क्रेडिट
 - viii. कार्यक्रम सं. 9: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा निर्यात क्रेडिट
4. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त स्कीमें क्रियात्मक सब्सिडीज हैं क्योंकि इनमें संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों या ऐसे संबंधित देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों जिनमें सार्वजनिक निकाय शामिल हैं, से वित्तीय योगदान शामिल हैं और ये प्राप्तिकर्ता (कर्ताओं) को लाभ प्रदान करती हैं। उनपर कुछ विशिष्ट उपक्रमों या उपक्रमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित रहने और इसलिए विशिष्ट और प्रतिकारी होने का आरोप है। उनपर कुछ मामलों में आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं और/या निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक होने का आरोप भी लगाया गया है।
5. निर्दिष्ट प्राधिकारी को अन्य सब्सिडीज की जांच करने का अधिकार प्राप्त है और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा जो विद्यमान पाई गई और प्राप्त की गई हैं।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

6. याचिकर्ताओं ने घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर सूचना उपलब्ध कराई है जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई क्षति को दर्शाते हैं।

ड. जांच की शुरुआत

7. प्राधिकारी ने पाया है कि उत्पादन पर प्रतिकारी शुल्क योग्य सब्सिडीज की विद्यमानता और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की मौजूदगी के प्रथमदृष्टया प्रमाण विद्यमान हैं और ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयात अपनी मात्रा और कीमत प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं।

8. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी एतद् द्वारा कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और प्रतिकारी शुल्क की मात्रा, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता, की सिफारिश करने के लिए ऊपर नियमावली के नियम 6 की शर्तों में घरेलू उद्योग को परिणामी महत्वपूर्ण क्षति की एतद् द्वारा जांच आरंभ करते हैं।

च. घरेलू उद्योग

9. आवेदन ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईवोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और रुशिल डेकोर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख समानुपात ठहरता है। इसलिए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि वर्तमान आवेदन में घरेलू उत्पादकों के घटक नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग ठहरता है और आवेदन ऊपर नियमावली के नियम 6(3) की शर्तों में स्थायी होने के मापदंड को पूरा करता है।

छ. विचाराधीन उत्पाद

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रेसिन या अन्य आर्गेनिक पदार्थों के साथ जोड़े गए या बिना जोड़े गए लकड़ी या अन्य चमकदार काष्ठीय सामग्री के फाइबर बोर्ड" हैं (जिन्हें यहां संबंधित वस्तुएं कहा गया है)।
11. फाइबर बोर्ड इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट का एक प्रकार है जो वुड फाइबर्स से निर्मित होता है। फाइबर प्रकारों में मध्यम-घनत्व फाइबर बोर्ड (एम डी एफ) और हार्ड बोर्ड (उच्च घनत्व फाइबर बोर्ड, एच डी एफ) शामिल हैं।
12. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 44.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित एच एस कोड के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य उत्पाद है :

4411	लकड़ी या अन्य काष्ठीय सामग्री का फाइबर बोर्ड, चाहे वह उसके साथ आवद्ध किया गया हो अथवा नहीं।
	- माध्यमिक घनत्व वाला फाइबर बोर्ड (एम डी एफ)
4411 12	-- अधिकतम 5 मि.मी. की मोटाई वाला
4411 13	-- 5 मि.मी. से अधिक किंतु 9 मि.मी. से कम मोटाई वाला
4411 14	-- 9 मि.मी. से अधिक मोटाई वाला
	- अन्य:
4411 92	-- 0.8 जी एम/से.मी. ³ से अधिक घनत्व वाला
4411 93	-- 0.5 जी एम/से.मी. ³ से अधिक किंतु 0.8 जी एम/से.मी. ³ से अनधिक घनत्व वाला
4411 94	--अनधिक 0.5 जी एम/से.मी. घनत्व वाला

13. पी यू सी में लेमिनेटिड और गैर लेमिनेटिड प्रकारों में एच डी एफ और एम डी एफ दोनों शामिल हैं। मोटाई/भार मापदंडों से संबंधित पी यू सी का वर्णन संगत आई टी सी (एच एस) के अंतर्गत किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

14. प्राधिकारी निम्नलिखित पी सी एन के अनुसार पी यू सी पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं:

4411 12	अनधिक 5 मि.मी. की मोटाई वाला एम डी एफ
4411 13, 4411 93	5 मि.मी. से अधिक किंतु 9 मि.मी. से अनधिक और 0.5 जी एम/से.मी. ³ से अधिक किंतु 0.8 जी एम/से.मी. ³ से अनधिक घनत्व वाला
4411 14	9 मि.मी. से अधिक मोटाई का एम डी एफ
4411 92	0.8 जी एम/से.मी. ³ से अधिक घनत्व वाला एच डी एफ

15. हितबद्ध पक्षकारों से इस अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पी सी एन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

16. विचाराधीन उत्पाद, के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं –

क. फ्लोरिंग बोर्ड

ख. सनमाइका

ग. इंसुलेशन बोर्ड

घ. कॉयर बोर्ड

ङ. जूट फाइबर बोर्ड

ज. समान वस्तु

17. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि तकनीकी और व्यापारिक रूप से दोनों प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना गया है।

झ. शामिल देश

18. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ शामिल देश इंडोनेशिया, मलेशिया, श्री लंका, थाइलैंड और वियतनाम है।

ञ. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 महीने) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और पी ओ आई की अवधि शामिल होगी।

ट. कार्य विधि और सूचना प्रस्तुत करना

20. संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में संबद्ध उत्पाद के संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्तों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए अलग रूप से सूचित किया जा रहा है। वर्तमान जांच में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक कोई अन्य पक्षकार भी इस पते पर लिख सकते हैं:

महानिदेशक

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

21. ऊपर नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी जाचांधीन उत्पाद, औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं जो सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर जांच से संगत अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

क. समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम 40 (चालीस) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुँच सके। तथापि, संबद्ध देशों की सरकारों, ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को, जिन्हें अलग से सूचना भेजी जा रही है, द्वारा उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिनों के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती या प्रस्तुत की गई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसरण में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करा सकते हैं।

ख. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. नियमावली के नियम 8 की शर्तों में, हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सेट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी सॉफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।
24. किसी "गोपनीय" अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सका है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई है और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक गोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ग. असहयोग

29. नियम 7(8)की शर्तों में यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

घ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2019

Case No. OI (CVD)- 6/2019

Subject: Initiation of Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Fiberboards from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

F.No. 6/17//2019- DGTR: Whereas Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited (hereinafter referred to as “petitioners” or “Domestic industry”) have filed an application on behalf of Domestic industry before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of Fiberboards (hereinafter referred to as the subject goods), from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Allegation of Subsidization

2. The petitioners have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject countries, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘Public bodies’. The petitioners have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

In terms of Article 13 of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), invitations for pre-initiation consultations were sent to the Government of Indonesia, Government of Malaysia, Government of Sri Lanka, Government of Thailand and Government of Vietnam. While consultations were held with the Government of Malaysia (GoM), Government of Indonesia (GoI) and Government of Vietnam (GoV) on 9th, 10th and 11th October 2019 respectively, the Government of Thailand did not avail the opportunity for consultations. The written submission of representatives of the responding Government of subject countries have been taken on record.

C. Subsidy Programs

3. The prima facie evidence provided by the petitioners shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the Government of respective subject countries and/or their respective public bodies as listed below-

a. **Schemes by Government of Indonesia –**

- i. Program 1: Provision of Standing Timber for Less Than Adequate Remuneration
- ii. Program 2: Government prohibition of Log exports
- iii. Program 3: Benefits for export facilitation by Indonesia EXIM Bank
- iv. Program 4: Reduction of Income tax
- v. Program 5: Exemption of import duty
- vi. Program 6: Exemption of import duty – Raw materials
- vii. Program 7: Exemption of VAT
- viii. Program 8: Accelerated depreciation or amortization
- ix. Program 9: Relief from Land and Building tax

b. **Schemes by Government of Malaysia –**

- i. Program No. 1: The Market Development grant
- ii. Program No. 2: Export Credit Refinancing
- iii. Program No. 3: Buyer Credit Guarantee
- iv. Program No. 4: Pioneer Status
- v. Program No. 5: Investment Tax Policies
- vi. Program No. 6: Reinvestment Allowance
- vii. Program No. 7: Accelerated Capital Allowance
- viii. Program No. 8: Tariff Related Incentives
- ix. Program No. 9: Allowance for plants and Machinery
- x. Program No. 10: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor
- xi. Program No. 11: Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
- xii. Program No. 12: Sales Tax Exemption
- xiii. Program No. 13: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
- xiv. Program No. 14: Double Deduction for Promotion of Exports
- xv. Program No. 16: Incentives for Small and Medium Enterprises
- xvi. Program No. 17: Allowance for Increased Export
- xvii. Program No.18: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

c. **Schemes by Government of Sri Lanka –**

- i. Program No. 1: National Building Tax exemption (Indirect Tax)
- ii. Program No. 2: Exemptions for custom duties on Capital and Intermediate Goods

- iii. Program No. 3: Income Tax Concessions for Specified undertakings
- iv. Program No. 4: Income tax exemptions for undertakings with high Investment
- v. Program No. 5: National Fertilizer Subsidy Scheme
- vi. Program No. 6: Subsidies for Rubber plantation

d. **Schemes by Government of Thailand –**

- i. Program No. 1: Exemption/reduction of import duties on machinery
- ii. Program No. 2: Exemption of import duty on raw material imported for use in production for export
- iii. Program No. 3: Reduction of import duty for raw or essential materials
- iv. Program No. 4: Exemption of Corporate Income Tax for BOI-Promoted Activities
- v. Program No. 5: Reduction of Income tax in Investment Promotion Zones
- vi. Program No. 6: Additional 25 percent deduction of the cost of installation or construction of facilities
- vii. Program No. 7: Double deduction available for companies in Investment Promotion Zones
- viii. Program No. 8: Exemption of Income tax – Dividends
- ix. Program No. 9: VAT exemption on exports
- x. Program No. 10: Short term Export Credit Insurance
- xi. Program No. 11: Medium and Long term Export credit Insurance

e. **Schemes by Government of Vietnam –**

- i. Program No. 1: Import Duty Exemptions on Imports of Raw Materials for Exporting Goods
- ii. Program No. 2: Import Duty Exemptions on Imported Raw Materials in non-tariff zones
- iii. Program No. 3: Import Duty Exemption on Imports of Spare Parts and Accessories for Companies in Industrial Zones
- iv. Program No. 4: Reduction of Corporate Income tax
- v. Program No. 5: Exemption or Reduction of Import tax
- vi. Program No. 6: Exemption and Reduction of Land & Water rent
- vii. Program No. 8: Investment Credit by Vietnam Development Bank
- viii. Program No. 9: Export Credit by Vietnam Development Bank

4. It has been alleged that the above schemes are actional subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the respective subject countries or other regional or local Governments of such respective countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
5. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

D. Allegation of Injury and Casual Link

6. The petitioners have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioner's prima facie shows material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject countries.

E. Initiation of the Investigation

7. The Authority finds that there is prima facie evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects.
8. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry

9. The application has been filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited, as per the evidence available on record, production of the petitioners accounts for major proportion of the total domestic production. The Authority, therefore, determines that the constituent of domestic producers in the present application constitute domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rules 6(3) of the Rules supra.

G. Product Under Consideration

10. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances" (hereinafter referred to as subject goods).
11. Fibreboards is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Types of fibreboard include medium-density fiberboard (MDF) and hardboard (high-density fiberboard, HDF).
12. The product is classified under heading 44.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The scope of the product under consideration is the products classifiable under following HS codes:

4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with
	- Medium density fibre board (MDF)
4411 12	-- Of a thickness not exceeding 5mm
4411 13	-- Of a thickness exceeding 5mm but not exceeding 9mm
4411 14	-- Of a thickness exceeding 9mm
	- Other:
4411 92	-- Of a density exceeding 0.8 gm/cm ³
4411 93	-- Of a density exceeding 0.5 gm/cm ³ but not exceeding 0.8 gm/cm ³
4411 94	-- Of a density not exceeding 0.5 gm/cm ³

13. The PUC covers both HDF and MDF in laminated and non-laminated forms. The delineation of the PUC with respect to thickness/weight parameters is done under the relevant ITC (HS) as stated above.

14. The Authority proposes to consider the PUC as per the following PCNs:

4411 12	MDF of a thickness not exceeding 5mm
4411 13, 4411 93	MDF of a thickness exceeding 5mm but not exceeding 9mm and of a density exceeding 0.5 gm/cm ³ but not exceeding 0.8 gm/cm ³
4411 14	MDF of a thickness exceeding 9mm
4411 92	HDF of a density exceeding 0.8 gm/cm ³

15. The interested parties are requested to furnish their comments on the proposed PCNs within 15 days from the date of this notification.

16. Following are excluded from the scope of the product under consideration –

- a) Flooring boards
- b) Sunmica
- c) Insulation board
- d) Coir boards
- e) Jute fibre board

H. Like Article

17. The petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from subject countries. The petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like articles' of the subject goods imported from the subject countries.

I. Countries Involved

18. The countries involved for the purpose of current investigation are Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

J. Period of Investigation

19. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2018 to March, 2019 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the POI.

K. Procedure & Submission of Information

20. The exporters in the subject countries, importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to provide all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110001

21. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to represent consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and casual link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limits set out below.

L. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of subject countries, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the response to questionnaire within 40 (forty) days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

M. Submission of Information on Non-Confidential basis

23. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
24. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

N. Non-cooperation

29. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

O. Inspection of Public File

30. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Designated Authority